LOK SABHA

Tuesday, April 5, 1966/Chaitra 15, 1888 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Agricultural Education in Universities

\+

*951. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Shree Narayan Das:
Shri Bade:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state:

(a) whether any assessment has been made with a view to find out as to what extent various Universities in the country have been able to give greater attention to agricultural education;

(b) if so, the result of such assessment; and

(c) whether any, if so, what steps have been taken with a view to encourage the Universities to give attention to **agricultural education?**

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) to (c). A statement giving the required information is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-5975/66].

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये केन्द्र किन किन राज्यों में खोले जाएंगे और इन की क्या विशेषताएं होंगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : आठ राज्यों में ये यूनीवरसिटियां खोल दी गई हैं और चौथी योजनामें चार और राज्यों, मद्रास, गुजरात, महाराष्ट्र और असम में खोली जाएंगी । इन की विशेषता यह होगी कि इन के अन्दर रिसर्च और एक्सटेंशन का कम्बाइंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन विश्वविद्यालयों से प्रति वर्ष कितने विद्यार्थी शिक्षा ले कर अपने क्षेत्र में कम करने निकलेंगे ?

श्री श्यामधर मिश्र : अभी इन आठ विश्वविद्यालयों के छात्रों की संख्या मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह संख्या पांच सौ के अन्दर होगी । इसके अलावा और भी कालिज हैं, अंडर ग्रेजुएट कालिज, ग्रेजुएट कालिज और पोस्ट ग्रेजुएट कालिज, जिनमें सालाना एडमिशन करीब दस हजार होगा ।

Shri C. K. Bhattacharyya: Agricultural universities are being established in almost every State. Has the Government taken any steps to impress upon the other universities that it is better to have agricultural education concentrated in the agricultural universities rather than having agricultural faculties in all the universities which will only result in diffusing the educational resources?

Shri Shyam Dhar Misra: On this general question, the Education Commission has been appointed by the Ministry of Education. They have appointed a task force which is going into the matter. The Commission is expected to complete its work in the near future, and they will give their views on this.

श्री बागड़ी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि का ज्ञान देने का माध्यम, प्रान्तीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, क्या हिन्दी भाषा रखेंगे या इसका माध्यम अंग्रेजी भाषा रखेंगे जिसका भारत की कृषि से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री श्यामधर मिश्र : जहां तक बेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कालिजों का सम्बन्ध है उनमें शिक्षा का माध्यम हर राज्य में अंग्रेजी है। लेकिन जहां तक फारमर्स की एजुकेशन का सवाल है, जो कि लोकल बिग्स के अधीन है, उसमें उस प्रान्त विशेष के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है, जैसे हिन्दी भाषी राज्यों में यह माध्यम हिन्दी होगी और तमिल राज्य में तमिल होगी।

Shrimati Akkamma Devi: In order to make the best use of the indigenous experience and knowledge, may I know whether the Government will give preference to students from agricultural families when admissions to agricultural colleges are being considered?

Shri Shyam Dhar Misra: That is exactly the policy.

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : क्या भारत सरकार उन विद्यार्थियों के लिए, जो कि इन विश्वविद्यालयों से बी० एस सी० और एम० एस० सी की डिगरियां ले कर निकलतेहैं, यह आवश्यक करेगी कि जो विद्यार्थी बी० एस सी० या एम० एस० सी० करने से पहले इस समय फसल की कटाई में आठ घंटे लगातार पन्द्रह दिन तक भाग ले, बादवा में आठ घंटे तक लगातार हल चलाए और जाड़े में आठ घंटे लगातार रात में खेत में पानी दे उसी को डिगरी दी जाएगी ?

Mr. Speaker: Suggestion for action.

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार के पास इस प्रकार के आंकड़े हैं कि इस वक्त कितने बी०एस सी० और एम०एस सी० एग्रीकल्चर वाले बेरोजगार हैं ? जब पहले ही हमारे इतने लोग बेकार हैं तो फिर और इन बेकारों की फौज को क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं उनको खेत में ले जा कर प्रेक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती ?

श्री श्यामधर मिश्र : जहां तक प्रेक्टिकल ट्रेनिंग का सवाल है, इन यूनीवरसिटियों में और कालिजों में प्रेक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है और उसके साथ ही थ्योरिटिकल शिक्षा भी दी जाती है। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, यह बात सही है कि थोड़े से लोग बेकार हैं लेकिन हमारी चौथी पंच वर्षीय योजना की ऐसे लोगों की आवश्यकता 30 हजार ग्रेजुएट की होगी और तीसरी योजना में इनकी उपलब्धि बीस हजार है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इन की आवश्यकता नहीं है।

श्री यशपाल सिंह : कितने बेरोजगार बी०एस सी०और एम०एस सी० एग्रीकल्चर हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर।

Shri P. Venkatasubbaiah: May I know whether the Government is aware of the fact that many of these people, especially these VLWs and those in the extension services are not experienced in agricultural methods with the result that even though large amounts are being spent on extension, the farmer is not getting the benefit of agricultural education? If so, does the government propose to train up these people sufficiently so as to impart training in farmer's practical agricultural work?

Shri Shyam Dhar Misra: It is a fact that the VLWs in the VLW training centres did not originally have that much agricultural orientation. However, now it has been decided that all the VLWs to be trained during the Fourth Plan will be given intensive training in agriculture, and to the extent they are qualified they will also

be trained in the colleges so that they can also get graduate's degree.

Shri S. M. Banerjee: In the statement it is stated that the central government on their part have also proposed larger allocations in the central sector in the Fourth Plan for basic agricultural education. It seems eight universities have been established or are likely to be established. What is the total financial aid to be given by the Centre during the Fourth Plan to these universities in various states?

Shri Shyam Dhar Misra: The total financial aid provided by the central government is Rs. 29 crores.

Company Law

\+

*952. **Shri Yashpal Singh:**
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Bagri:

Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal under consideration to change the Company Law in the context of the rapid industrial development in the country; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) No such proposal is at present under consideration.

(b) Does not arise.

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार ने इस तरह का कोई तरीका अपनाया है कि ये कम्पनी वाले ब्लैक मनी न बढ़ा सकें और ये जो टैक्स एवाइड करते हैं इसको रोका जा सके ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : श्रीमन्, यह जो सवाल किया गया है यह इनकम टैक्स ऐक्ट और फाइनेन्स के मुताल्लिक है, और इस ऐक्ट में काफी ऐसी दफात मौजूद हैं जो कि ब्लैक मनी के खिलाफ और टैक्स इवेजन के खिलाफ काम में लायी जा सकती हैं और लायी जाती भी हैं ।

श्री यशपाल सिंह : इसी आदरणीय सदन में माननीय मंत्री जी ने यह वायदा किया था कि मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम को बिल्कुल एबालिश करेंगे, पर अभी तक न तो ऐसा करने की डेट बतलायी है और न यह बतलाया है कि इस के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम डिसकरेज होता जा रहा है, उसमें कमी होती जा रही है खुद ब खुद । और कम्पनीज ऐक्ट की दफात 324 और 326 पर सरकार अमल कर रही है, और अब भी मैनेजिंग एजेंसीज बढ़ायी जा रही हैं वे बहुत कम बढ़ाई जा रही हैं, और जो प्रेस नोट इश्यू हुआ है उस पर अमल करने की कोशिश की जा रही है ।

Shri Daji: Has it come to the notice of government that even while the committee is still considering and a final decision has yet to be taken, certain managing agencies were given hurried extensions upto 15 years so that whatever decision might come in these cases, the decision has already been made by the government? Has the government taken notice of it and, if so, is it going to revise it? If not why were extensions given for fifteen years?

Shri G. S. Pathak: Government has taken notice of the fact that before the issue of the Press note dated the 31st December, 1965 certain extensions had been given. It has not been possible for me so far within the short period that I have been law minister to examine why and for how long extensions were given in some cases. They were not given in all the cases.

Shri Daji: It is therefore discriminatory.

Shri G. S. Pathak: For aught I know there may be very good reasons.

Shri Surendranath Dwivedy: Will you re-examine it?